SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

INDIAN POLITY BY-

SUJEET BAJPAI SIR

Question No: 1

SAFALTA CLASS™ An Initiative by अमर उजाला

The writ which may be filed for protection of right to Personal Freedom is –

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट (writ) याचिका दायर की जा सकती है?

(a) Mandamus

(b) Quo-warranto

(c) Habeas Corpus

(d) Certiorari

Question No: 2

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

The Supreme Court of India has propounded the 'Doctrine of Basic Structure of the Constitution in which of the following cases?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत (बुनियादी ढांचा सिद्धांत) का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है?

(a) Golaknath Vs. Punjab State

(b) Sajjan Singh Vs. Rajasthan State

(c) Keshavanand Bharti Vs. Kerala State — 1973

(d) Shankari Prasad Vs. Indian Union

Question No: 3

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

12

The President nominates twelve members of the Rajya Sabha on the basis of

(a) their performance as office bearers of cultural societies

(b) their role played in political setup of the country

(c) the recommendation made by the Vice-president

(d) their distinction in the field of science, art, literature and social service.

Question No: 3

राष्ट्रपति ने राज्यसभा के बारह सदस्यों को आधार पर मनोनीत किया
(क) सांस्कृतिक क्षेत्र के पदाधिकारियों के रूप में उनका प्रदर्शन
(ख) देश के राजनीतिक क्षेत्र में निभाई गई उनकी भूमिका
(ग) उपराष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिश +
(घ) विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान ।

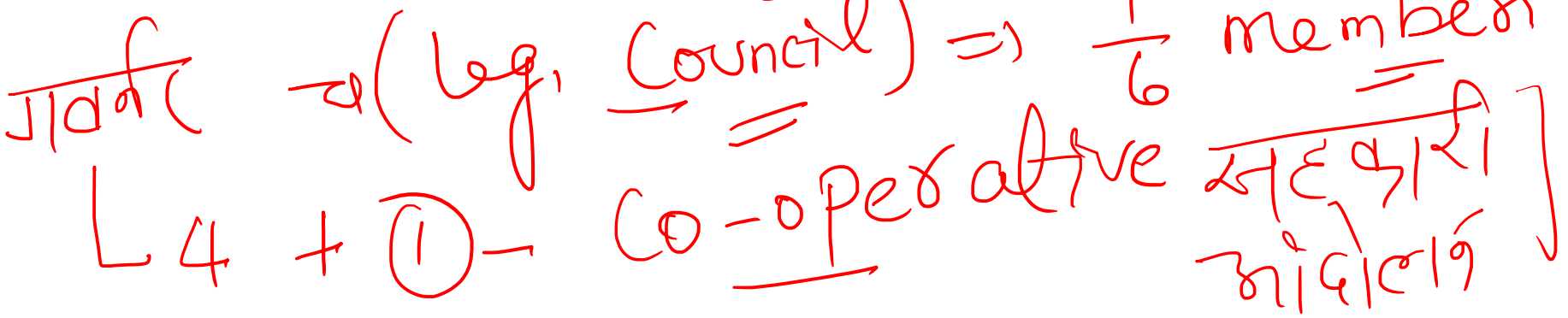

Question No: 4

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

The word ‘Budget’ is mentioned in which of the following Articles of the Constitution of India:

भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमे बजट शब्द का उल्लेख किया गया है:

(a) Art. 266

(b) Art. 112

(c) Art. 267

(d) None

Question No: 5

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Which of the following statements are incorrect?

1. Rajya Sabha can reject a Money Bill.
2. Rajya Sabha can make recommendations on a Money Bill.
3. Rajya Sabha cannot reject a Money Bill.
4. Rajya Sabha should return the Money Bill to the Lok Sabha within 14 days.
5. Rajya Sabha can amend a Money Bill.

Question No: 5

निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं?

1. राज्यसभा मनी बिल को रद कर सकती है।
2. राज्यसभा मनी बिल पर सिफारिशें कर सकती है।
3. राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती।
4. राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर लोकसभा में धन विधेयक वापस करना चाहिए।
5. राज्यसभा मनी बिल में संशोधन कर सकती है।

Question No: 5

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

(a) 2, 3 and 4

(b) 1, 2 and 5

(c) 1 and 5

(d) only 1

Question No: 6

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Who among the following was the advisor of the Drafting Committee of the Constituent Assembly?

निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति का सलाहकार था?

(a) B. Shiva Rao

(b) Dr. B.R. Ambedkar — Pres. of Drafting Comm.

(c) Sachidananda Sinha

(d) B.N. Rao

Question No: 7

The idea of including the Emergency provisions in the Constitution of India has been borrowed from the.

भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार से उधार लिया गया है

(a) Constitution of Canada

(b) Weimar Constitution of Germany

(c) Constitution of Ireland

(d) Constitution of the USA

FR + Preamble

Question No: 8

The Speaker of the Lok Sabha can resign his office by addressing his resignation to.

लोकसभा अध्यक्ष.....को संबोधित करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं.

(a) the President

(b) the Prime Minister

(c) the Deputy Speaker of the Lok Sabha

(d) the Chief Justice of India

Question No: 9

Art-61

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Who can initiate impeachment proceedings against the President of India?

भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है?

(a) Only Lok Sabha

(b) Only Rajya Sabha

(c) Either House of the Parliament

(d) Any Legislative Assembly

Question No: 10

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Public Interest Litigation (PIL) may be linked with.

जनहित याचिका (पीआईएल) के साथ जोड़ा जा सकता है

(a) judicial review

(b) judicial activism

(c) judicial intervention

(d) judicial sanctity

Jurisdiction and Powers of Supreme Court

1. Original Jurisdiction.
2. Writ Jurisdiction.
3. Appellate Jurisdiction.
4. Advisory Jurisdiction.
5. A Court of Record.
6. Power of Judicial Review.
7. Other Powers.

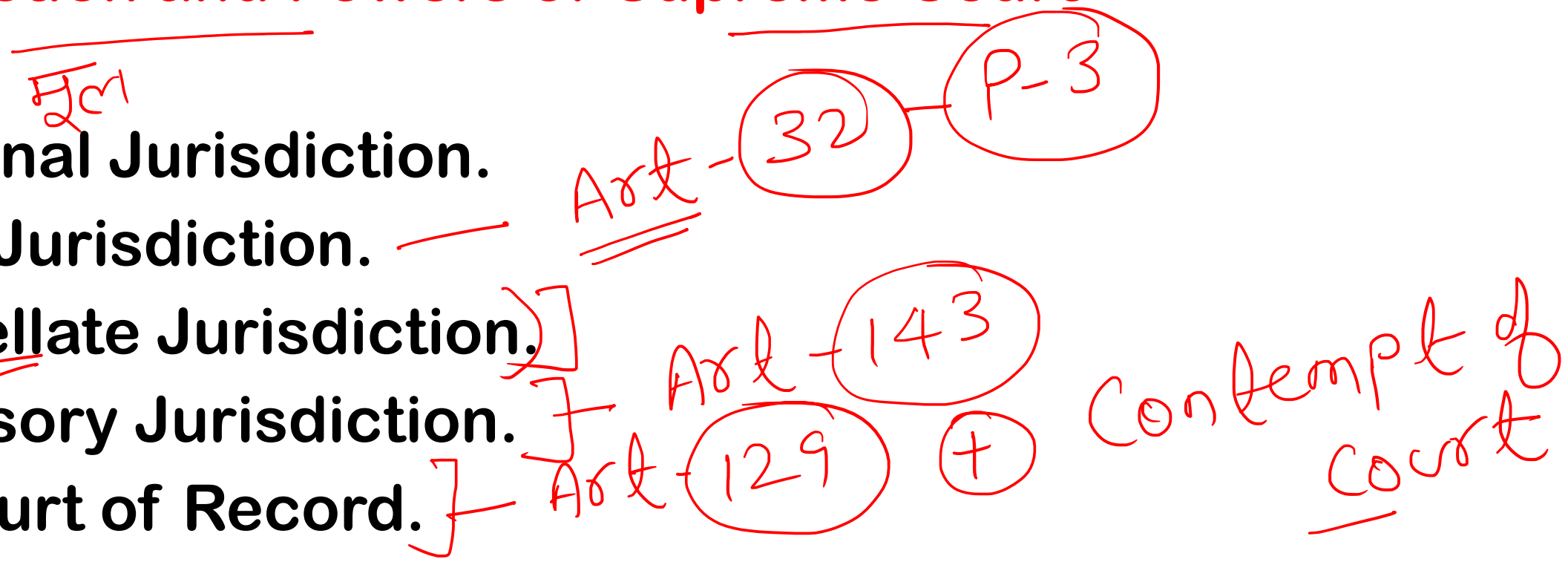

सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां

1. मूल क्षेत्राधिकार।
2. रिट क्षेत्राधिकार।
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
4. सलाहकार क्षेत्राधिकार।
5. रिकॉर्ड की एक अदालत ।
6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति।
7. अन्य शक्तियां।

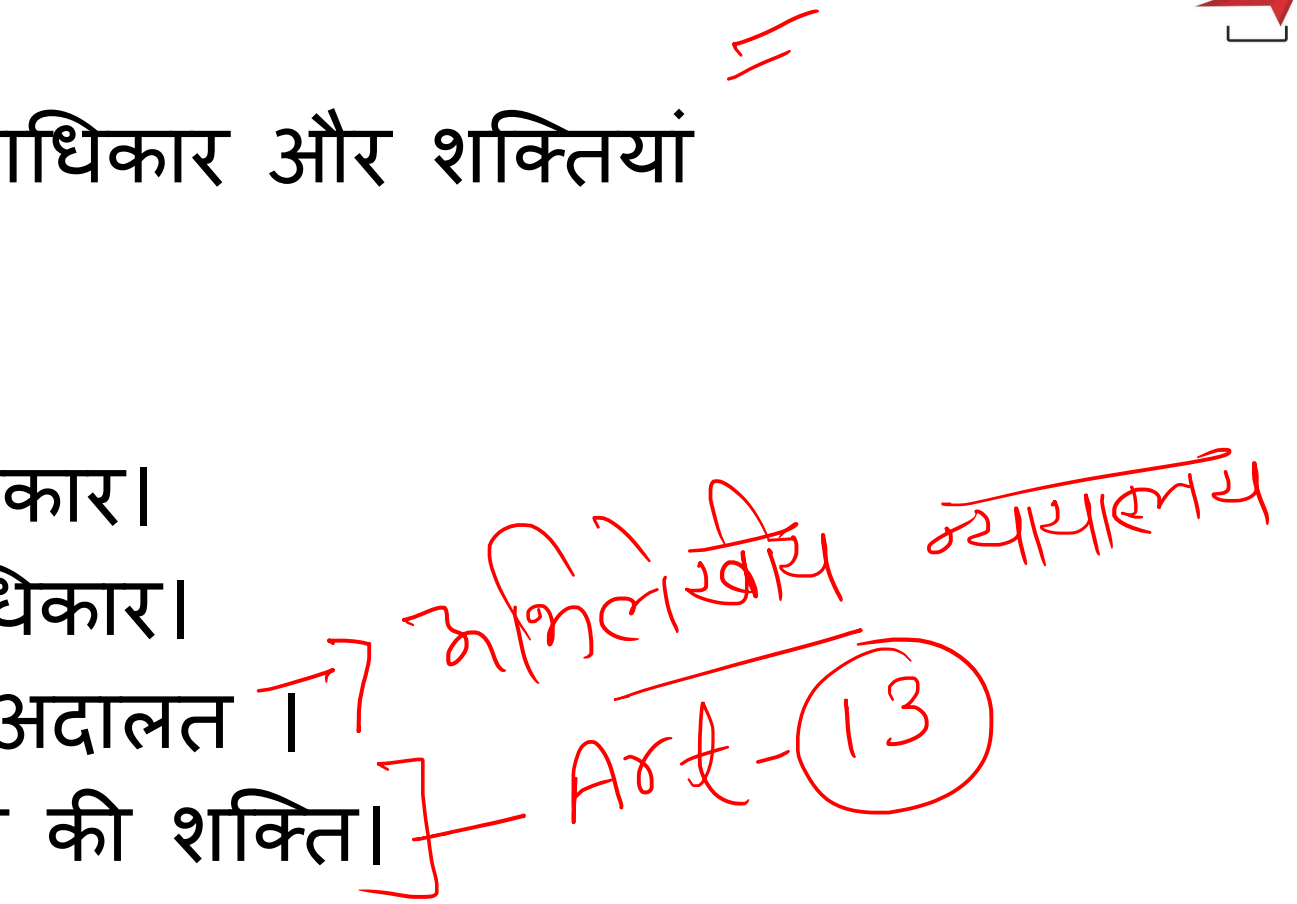

1. Original Jurisdiction

As a federal court, the Supreme Court decides the disputes between different units of the Indian Federation. More elaborately, any dispute between:

(a) the Centre and one or more states; or

1. मूल क्षेत्राधिकार

संघीय अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट भारतीय महासंघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से, के बीच किसी भी विवाद:

(क) केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य; या

(b) the Centre and any state or states on one side and one or more states on the other; or

(c) between two or more states.

(ख) केंद्र और एक तरफ कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य; या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ।

2. Writ Jurisdiction

The Constitution has constituted the Supreme Court as the guarantor and defender of the fundamental rights of the citizens.

2. रिट क्षेत्राधिकार

संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का गठन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर और रक्षक के रूप में किया है।

However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive.

The high courts are also empowered to issue writs for the enforcement of the Fundamental Rights.

It means, when the Fundamental Rights of a citizen are violated, the aggrieved party has the option of moving either the high court or the Supreme Court directly.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का भी अधिकार है ।

इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ले जाने का विकल्प होता है।

There is also a difference between the writ jurisdiction of the Supreme Court and that of the high court.

The Supreme Court can issue writs only for the enforcement of the Fundamental Rights and not for other purposes.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में भी अंतर है।

उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है न कि अन्य प्रयोजनों के लिए।

The high court, on the other hand, can issue writs not only for the enforcement of the fundamental rights but also for other purposes. It means that the writ jurisdiction of the high court is wider than that of the Supreme Court.

दूसरी ओर, उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है ।

इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है।

3. Appellate Jurisdiction

The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgements of the lower courts.

It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads:

(a) Appeals in constitutional matters.

(b) Appeals in civil matters.

(c) Appeals in criminal matters.

(d) Appeals by special leave.

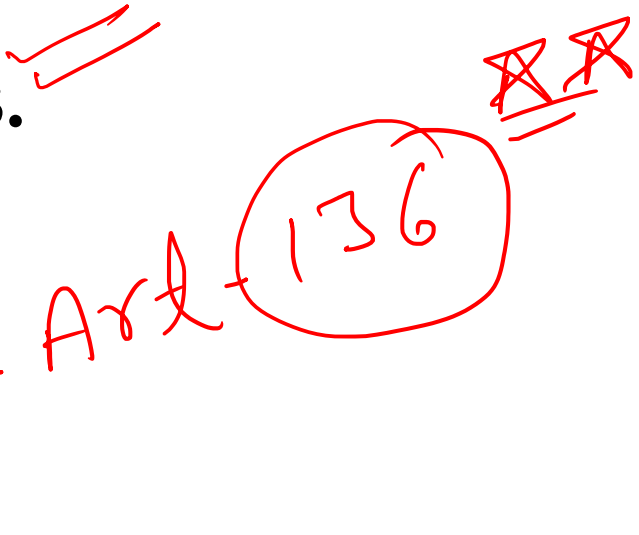

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार

सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से अपील की अदालत है और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है ।

यह एक व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार है जो चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है प्राप्त है:

(क) संवैधानिक मामलों में अपील।

(ख) सिविल मामलों में अपील ।

(ग) आपराधिक मामलों में अपील।

(घ) विशेष अवकाश द्वारा अपील ।

4. Advisory Jurisdiction

The Constitution (Article 143) authorises the president to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:

(a) On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise.

(b) On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanador other similar instruments

4. सलाहकार क्षेत्राधिकार संविधान (अनुच्छेद १४३)

राष्ट्रपति को मामलों की दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए अधिकृत करता है:

(क) कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है ।

(ख) किसी भी पूर्व संविधान संधि, समझौते, वाचा, सगाई, संयोजिका अन्य समान साधनों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर

In the first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the president. But, in the second case, the Supreme Court 'must' tender its opinion to the president.

In both the cases, the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory and not a judicial pronouncement.

Hence, it is not binding on the president; he may follow or may not follow the opinion.

पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट टेंडर कर सकता है या राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है ।

लेकिन, दूसरे मामले में, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय का टेंडर देना चाहिए ।

दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी है न कि न्यायिक घोषणा। इसलिए, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है; वह का पालन करें या राय का पालन नहीं कर सकते हैं ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Justice Fathima Beevi became the first female judge who was appointed to the Supreme Court of India in 1989.

High Courts in India

Justice Anna Chandy: The First Female High Court Judge Of India

केरल

It is also contested that she is most likely the second woman in the world to become a high court judge after USA's Florence Allen who was appointed as a judge in 1922.

यह भी विरोध किया है कि वह सबसे अधिक संभावना दुनिया में दूसरी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरेंस एलन जो १९२२ में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गई है ।

Leila Seth

— Ist woman → chief Justice of Any HC (Himanchal HC)

Leila Seth (20 October 1930 – 5 May 2017) was the first woman judge on the Delhi High Court and she became the first woman to become Chief Justice of a state High Court on 5 August 1991.

लीला सेठ (20 अक्टूबर 1930 - 5 मई 2017) दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला जज थीं और वह 5 अगस्त 1991 को किसी राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनीं।

List of High Courts in India			
Year	**Name**	**Territorial Jurisdiction**	**Seat & Bench**
1862	Bombay	Maharashtra Dadra & Nagar Haveli Goa Daman Diu	Seat: Mumbai Bench: Panaji, Aurangabad, and Nagpur
1862	Kolkata	West Bengal Andaman & Nicobar islands	Seat: Kolkata Bench: Port Blair
1862	Madras	Tamil Nadu Pondicherry	Seat: Chennai Bench: Madurai

1866	Allahabad	Uttar Pradesh	Seat: Allahabad Bench: Lucknow
1884	Karnataka	Karnataka	Seat: Bengaluru Bench: Dharwad and Gulbarga
1916	Patna	Bihar	Patna
1928	Jammu & Kashmir	Jammu & Kashmir	Srinagar and Jammu

1948	Guwahati	Assam Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh	Seat: Guwahati Bench: Kohima, Aizawl, and Itanagar
1949	Odisha	Odisha	Cuttack
1949	Rajasthan	Rajasthan	Seat: Jodhpur Bench: Jaipur
1956	Madhya Pradesh	Madhya Pradesh	Seat: Jabalpur Bench: Gwalior and Indore
1958	Kerala	Kerala & Lakshadweep	Ernakulam
1960	Gujarat	Gujarat	Ahmedabad
1966	Delhi	Delhi	Delhi

1971	Himachal Pradesh	Himachal Pradesh	Shimla
1975	Punjab & Haryana	Punjab, Haryana & Chandigarh	Chandigarh
1975	Sikkim	Sikkim	Gangtok
2000	Chattisgarh	Chattisgarh	Bilaspur
2000	Uttarakhand	Uttarakhand	Nainital
2000	Jharkhand	Jharkhand	Ranchi

2013	Tripura	Tripura	Agartala
2013	Manipur	Manipur	Imphal
2013	Meghalaya	Meghalaya	Shillong
2019	Telangana	Telangana	Hyderabad
2019	Andhra Pradesh	Andhra Pradesh	Amravati